

प्रेषक,

विनीता कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
समाज कल्याण, उत्तरांचल,  
हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, 16 नवम्बर 2006

विषय : अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेतालघाट, जनपद-नैनीताल, उत्तरांचल के भवन निर्माण हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1642/स.क./निर्माण/ 2006-07, दिनांक 02 अगस्त 2006 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेतालघाट, जनपद-नैनीताल, उत्तरांचल के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, इकाई-अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त रूपये 1,55,17,000/- (रूपये एक करोड़ पचपन लाख सत्रह हजार मात्र) की औचित्यपूर्ण धनराशि पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में रूपये 1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने से पूर्व निर्माण इकाई से विस्तृत मानचित्र आगणन में संलग्न माप के ब्यौरे के अनुसार मानचित्र गठित कर शासन को अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उक्त निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध भूमि श्री विभाग के नाम हस्तांतरित होने सम्बन्धी अभिलेख भी शासन को प्रमाणित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें 'शिड्यूल ऑफ रेट' में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितने कि स्वीकृत मानक हैं, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाए।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग और "MORTH" द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।
9. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए। एक मद की धनराशि दूसरी मदों में कदापि व्यय न की जाए।
10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में परीक्षण करा लिया जाए तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
11. जी.पी.बब्ल्यू फॉर्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जाएगा।
12. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किए जाएंगे। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाता है तो उसे अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे।
13. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।
14. स्वीकृत धनराशि का व्यय बजट मैन्युअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. कार्य कराने समय निविदा विषयक नियमों एवं मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।
16. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।
17. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक ही किया जाए।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।



19. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्यय की "अनुदान संख्या-30" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "4225-अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-91-जिला योजना-03-आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण (नया निर्माण)-आयोजनागत" के मानक मद "24-ग्रहण निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।
20. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-769/XXVII-3/2006, दिनांक 15 नवम्बर 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)  
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांक संख्या 532(1)/XVII(1)-01/2006-11(08)/2006, तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव-अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ, उत्तरांचल।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तरांचल।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
8. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल, उत्तरांचल।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल, उत्तरांचल।
10. अधिशारी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इकाई-अल्मोड़ा, उत्तरांचल।
11. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तरांचल शासन।
12. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. आदेश पंजीका।

अज्ञात से

(धीरेन्द्र सिंह दत्ताल)  
उप सचिव।